

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर  
डी.बी. सिविल अपील संख्या 4252/2017

पदम राज भंडारी पुत्र श्री अजीत राज भंडारी, निवासी 42, गली नं. 3, श्याम नगर, पाल  
लिंग रोड, जोधपुर - 342008।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 के माध्यम से।
2. प्रधान आयकर आयुक्त-2, पावटा सी रोड, जोधपुर - 342010
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-34, पावटा सी-रोड, जोधपुर - 342010

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री टी.सी. गुप्ता (वीसी के माध्यम से)  
प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सुनील भंडारी

---

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी  
माननीय श्री न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण  
आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

01/07/2024

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत का दावा करते हुए पेश की गई है:

"1. ऊपर वर्णित तथ्यों और आधारों के मद्देनजर, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, सीआईटी द्वारा पारित दिनांक 27.02.2017 के आदेश को कृपया रद्द किया जाए और अपास्त किया जाए तथा प्रतिवादियों को देरी को माफ करने और दावे के अनुसार धन वापसी की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए।

2. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जा सकता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जा सकता है।”

2. याचिकाकर्ता, जो एक बीमा सर्वेक्षक है, ने कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए रिफंड का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत देरी की माफी की मांग करते हुए 12.05.2016 को एक आवेदन दायर किया। हालांकि, प्रतिवादियों ने 27.02.2017 को देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री टी.सी. गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, जो अब लगभग 72 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, ने वास्तविक कठिनाई का सामना किया, और इस प्रकार, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत लाभ दिया जाना चाहिए था, जो कि 09.06.2015 (अनुलग्नक-3) के सीबीडीटी परिपत्र से संबंधित है।

3.1 विद्वान अधिवक्ता श्री गुप्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एम. मालानी बनाम आयकर आयुक्त एवं अन्य : सिविल अपील संख्या 5950/2008 (एस.एल.पी. (सी) संख्या 4091/2007 से उत्पन्न) के मामले में निर्धारित मिसाल कानून पर भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:

8. न्यू कोलिन्स कॉन्साइज इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार 'Genuine' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

'Genuine' का अर्थ है नकली या जाली नहीं, वास्तविक, दिखावा नहीं (न कि फर्जी या महज एक छल)'

उपर्युक्त प्रावधान की व्याख्या के लिए, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का सहारा लिया जाना चाहिए। ब्याज लगाना हालांकि वैधानिक प्रकृति का है, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ करदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर कर जमा न करने से होने वाले नुकसान से राजस्व की भरपाई के लिए। उक्त सिद्धांत को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से भी लागू किया जाना चाहिए कि कोई कठिनाई हुई है या नहीं। वास्तविक कठिनाई का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक कठिनाई होगा। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बड़ी संपत्ति रखने वाला व्यक्ति कभी कठिनाई में नहीं होगा क्योंकि

वह उन संपत्तियों को बेच सकता है और लगाए गए ब्याज की राशि का भुगतान कर सकता है।

वास्तविक कठिनाई के तत्वों को शब्दकोश में दिए गए अर्थ और उससे संबंधित कानूनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, एक अन्य प्रसिद्ध सिद्धांत, अर्थात्, कोई व्यक्ति अपने स्वयं के गलत कार्य का लाभ नहीं उठा सकता है, को भी ध्यान में रखना होगा। यह स्वीकार किया जाता है कि उक्त सिद्धांत को इस मामले में निचली अदालतों द्वारा लागू नहीं किया गया है, लेकिन हम कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को उजागर करने के लिए इस क्षेत्र में संचालित कुछ उदाहरणों पर ध्यान दे सकते हैं। [देखें प्रियंका ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1991 अनुपूरक (1) एससीसी 102, पैरा 39, भारत संघ और अन्य बनाम मेजर जनरल मदन लाल यादव (सेवानिवृत्त) (1996) 142 पर 4 एससीसी 127 , पैरा 28 एवं 29, अशोक कपिल बनाम सना उल्लाह (मृत) एवं अन्य. (1996) 6 एससीसी 342 एट 345, पैरा 7, सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार (2003) 8 एससीसी 673 एट 692, पैरा 65, प्रथम वाक्य, कुशेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। (2007) 11 एससीसी 447, पैरा 13, 14 और 16)।

इस प्रकार, हमारे विचार में, उक्त सिद्धांत को इस प्रकृति के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। एक वैधानिक प्राधिकरण इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के बावजूद चुप रह सकता था। उसे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसे अपीलकर्ता की प्रार्थना का जवाब देना चाहिए था।

हालांकि, एक अन्य सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, अर्थात्, एक वैधानिक प्राधिकरण को कानून के चारों कोनों के भीतर काम करना चाहिए। निस्संदेह, आयुक्त के पास करदाता के अनुरोध को स्वीकार न करने का विवेक है, लेकिन उस विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। उसे इस बात पर संतुष्ट होना होगा कि ब्याज माफ करने का

आदेश पारित करने से पहले उसमें निर्धारित तीन शर्तें पूरी हो गई हैं।

किसी भी अनुचित बकाया का भुगतान करने की बाध्यता अपने आप में कठिनाई का कारण बनेगी। लेकिन, फिर भी एक सवाल यह भी उठेगा कि क्या राशि के भुगतान में चूक ऐसी परिस्थितियों के कारण हुई जो करदाता के नियंत्रण से बाहर थीं।

दुर्भाग्य से, मामले के इस पहलू पर विद्वान आयुक्त और उच्च न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। विभाग ने दलील दी थी कि जब तक देय कर की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता, प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता था और डिमांड ड्राफ्ट को भुनाया नहीं जा सकता था। ब्याज लगाने के संबंध में करदाता के मामले में भी यही तर्क लागू होगा। यह कहना एक बात है कि कर की सही राशि का भुगतान न करने के आधार पर ब्याज लगाना करदाता के अनुरोध को स्वीकार न करने का आधार हो सकता है क्योंकि यह एक वैधानिक है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि आयुक्त की ओर से विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग के उद्देश्य से उक्त कारक पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से कहा कि प्रतिभूतियों को बेचा जाए। अपीलकर्ता के उक्त अनुरोध को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सका, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह अपीलकर्ता की ओर से स्वैच्छिक कार्य था।

यह ऐसा मामला भी नहीं था जिसमें अधिनियम की धारा 226 की उपधारा (3) का सहारा लिया गया हो। चूंकि प्रस्ताव स्वैच्छिक था, इसलिए किसी भी वैधानिक निषेधाज्ञा के अधीन विभाग के अधिकारी अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार कर सकते थे। संभवतः राजस्व के हित में ही अपनी बकाया राशि वसूलना था। यह कानून के तहत किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार नहीं किया गया है।

9. हालांकि, डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में अपीलकर्ता के पास यही आधार उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उसके संबंध में ऐसा कोई

अनुरोध नहीं किया गया था। डिमांड ड्राफ्ट एक कंपनी के नाम पर था। यह सच हो सकता है कि जब कोई दस्तावेज जब्त किया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह उस व्यक्ति का है जिसके कब्जे या नियंत्रण से इसे जब्त किया गया था, जैसा कि अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (4 ए) में निर्धारित है, लेकिन ऐसा अनुमान खंडनीय है। करदाता द्वारा स्वयं किए गए किसी अनुरोध के अभाव में, संभवतः उस समय, इसे भुनाया नहीं जा सकता था। अपीलकर्ता के पास कानून के अनुसार इसका स्वामित्व नहीं था। उसने इसके भुनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया।

इस तरह की धारणा बनाई जानी चाहिए या नहीं, यह आकलन अधिकारी द्वारा अंतिम आकलन करते समय विचार का विषय था, क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वयं अधिनियम की धारा 245 सी(1) के तहत निपटान आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया था।

10. इसलिए, हमारा मत है कि यदि आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाए और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए आयकर आयुक्त को भेज दिया जाए, तो न्याय के हित सुरक्षित रहेंगे।

4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री सुनील भंडारी ने प्रस्तुत किया कि आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के दायरे पर तभी विचार किया जा सकता था, जब वास्तव में कोई कठिनाई हो और वह भी केवल छह वर्षों की अवधि के लिए, जो आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के अनुसरण में सीबीडीटी परिपत्र संख्या 09/2015 दिनांक 09.06.2015 में निर्धारित है, जो देरी को माफ करने के लिए प्राधिकरण को अधिकतम छह वर्ष की शक्ति निर्धारित करता है।

4.1 श्री भंडारी ने दीप नारायण गुप्ता बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जो 2003 264 आईटीआर 251 पटना में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैरा 5 का संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार है:

“5. एकमात्र आधार, जिस पर वास्तविक कठिनाई में विस्तार दिया जा सकता है। इसे अधिनियम के तहत सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तविक कठिनाई है या नहीं,

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और इस उद्देश्य के लिए स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले में कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दिए गए मामले में, बेशक, रिटर्न समय से बहुत अधिक समय बाद दाखिल किए गए थे। रिटर्न दाखिल करने में देरी के बारे में याचिकाकर्ता की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, दूसरी ओर, बोर्ड ने पाया है कि यह अधिनियम के तहत देयता से बचने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से एक बहुत ही जानबूझकर किया गया प्रयास है। आदेश के पैराग्राफ 4 में विस्तृत कारण बताए गए हैं, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

“रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 31 मार्च, 1995 और 31 मार्च, 1996 से पहले थी। हालांकि, रिटर्न 9 अक्टूबर, 1998 को दाखिल किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मूल्यांकनकर्ता ने जानबूझकर अपने रिटर्न को नियत तिथि के बहुत बाद में दाखिल किया है ताकि वह जांच मूल्यांकन से बच सके। उदाहरण के लिए, मूल्यांकन वर्ष 1993-94 के लिए, मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ बहुत कम है। रिटर्न के साथ कोई ऑडिट रिपोर्ट संलग्न नहीं है। बैलेंस शीट में, मूल्यांकनकर्ता ने असुरक्षित ऋण और अन्य वित्त को देनदारियों के रूप में दिखाया है। रिटर्न की देरी से फाइलिंग स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मूल्यांकनकर्ता ने अपने खातों में हेराफेरी की है और विभाग द्वारा जांच मूल्यांकन को रोका है।”

4.2 विद्वान वकील श्री भंडारी ने आगे कहा कि करदाता ने पहले भी कर रिटर्न दाखिल किया था और वह रिफंड का दावा भी कर रहा था। उन्होंने यह भी जोरदार ढंग से कहा कि याचिकाकर्ता ने अवसाद या बीमारी के बारे में कोई सबूत नहीं दिया है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के साथ-साथ बार में उद्धृत मिसाल कानून के साथ-साथ रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि

याचिकाकर्ता अब 72 वर्ष का है और एक बीमा सर्वेक्षक के रूप में काम करता है और वह कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए कर रिटर्न दाखिल करना चाहता है।

6. आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(ख) नीचे पुनः उद्धृत की गई है:

“119. अधीनस्थ प्राधिकारियों को निर्देश.-

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,-

(ख) बोर्ड, यदि वह किसी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझता है, तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, 11[किसी आयकर प्राधिकारी को, जो आयुक्त (अपील) न हो] इस अधिनियम के तहत किसी छूट, कटौती, वापसी या किसी अन्य राहत के लिए आवेदन या दावे को स्वीकार करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद ऐसा आवेदन या दावा करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उससे निपटने के लिए अधिकृत कर सकता है;”

7. सीबीडीटी परिपत्र के प्रासंगिक भाग, विशेष रूप से, पैराग्राफ 3 और 5 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“3. रिफंड/नुकसान के दावे के लिए कोई भी माफ़ी आवेदन उस मूल्यांकन वर्ष के अंत से छह साल से अधिक समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके लिए ऐसा आवेदन/दावा किया गया है। छह साल की यह सीमा बोर्ड सहित उपरोक्त निर्धारित मौद्रिक सीमाओं के अनुसार देरी को माफ़ करने की शक्ति रखने वाले सभी अधिकारियों पर लागू होगी। माफ़ी आवेदन का निपटान उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया हो, जहाँ तक संभव हो।

5. ऐसे दावे के मामले में पी.सीसीएसआईटी/सीसीएसआईटी/पी.सीएसआईटी/सीएसआईटी को सौंपी गई मौद्रिक सीमाओं के भीतर आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

धारा 119(2) (बी) के तहत मामले पर विचार करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घोषित आय/हानि और/या दावा किया

गया रिफंड सही और वास्तविक है और यह भी कि मामला वास्तव में गुण-दोष के आधार पर कठिन है। मामले से निपटने वाले पी.सीसीआईटी/सीसीआईटी/पी.सीआईटी/सीआईटी को दावे की सत्यता का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने या मामले की जांच करने के लिए क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश देने का अधिकार होगा।”

8. इस न्यायालय ने प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कारण की जांच की है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी बीमा कंपनी से सर्वेक्षण शुल्क भुगतान से सीमित आय है। परिणामस्वरूप, वह प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ था। आरोपित आदेश इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि करदाता ने यह बयान दिया है कि वह उस अवधि के दौरान अवसाद में था, जो बुढ़ापे के साथ जुड़ा हुआ था।

9. इस न्यायालय ने प्रतिवादियों के इस प्रबल विरोध पर विचार किया कि इस मामले में कोई वास्तविक कठिनाई का कारण स्थापित नहीं किया गया है, और इस प्रकार, जब कानून का मुख्य शब्द यानी वास्तविक कठिनाई लागू नहीं होती है, तो आयकर अधिनियम की धारा 119 (2) (बी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, लेकिन यह न्यायालय इस तरह के प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

10. यह न्यायालय यह भी पाता है कि दीप नारायण गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक ऐसे करदाता से संबंधित है, जो जांच मूल्यांकन से बचने की कोशिश कर रहा है और राजस्व संग्रह के गलत पक्ष में था, और इस प्रकार, न्यायालय द्वारा लिया गया सख्त दृष्टिकोण एक अलग तथ्यात्मक आधार पर खड़ा है।

11. एक अन्य निर्णय, जो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, वह गुजरात इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का है, जो 2002 255 आईटीआर 396 गुजरात में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैराग्राफ 6 पर जोर दिया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर विचार किया है। हम यह कह सकते हैं कि प्रतिवादियों ने याचिका में किए गए कथनों का खंडन करते हुए कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-कंपनी का प्रधान

अधिकारी जून, 1991 के आसपास बिस्तर पर था, क्योंकि वह गंभीर तपेदिक से पीड़ित था और डॉक्टर ने उसे लगभग तीन महीने तक पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी थी। 1 अक्टूबर, 1999 के आवेदन में किए गए कथनों के अनुसार, याचिकाकर्ता-कंपनी के प्रधान अधिकारी ने तपेदिक का इलाज कराया था जो लगभग सात से आठ महीने तक चला था। उक्त आवेदन में किए गए कथनों से यह भी स्पष्ट है कि अप्रैल, 1992 के आसपास, कंपनी का प्रधान अधिकारी फिर से बीमार पड़ गया था और डॉक्टर ने बीमारी का निदान टाइफाइड के रूप में किया था और वह एक बार फिर बिस्तर पर बंधा हुआ था। चूंकि कंपनी के कराधान मामलों को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया जा सका, जिसमें रिफंड का दावा किया गया था। अधिनियम की धारा 119(2)(बी) बोर्ड को किसी भी आयकर अधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार देती है जो आयुक्त (अपील) नहीं है, जो आयकर अधिनियम के तहत किसी भी छूट, कटौती, रिफंड या किसी अन्य राहत के लिए आवेदन या दावे को स्वीकार करने के लिए आयकर अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद ऐसा आवेदन या दावा करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उपर्युक्त प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, बोर्ड ने 12 अक्टूबर, 1993 को परिपत्र जारी किया है, जो आयकर अधिकारी को रिफंड का दावा करने में हुई देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है। प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि उक्त परिपत्र में उल्लिखित चार शर्तें याचिकाकर्ता द्वारा पूरी नहीं की गई हैं, लेकिन रिफंड के लिए आवेदन केवल इस आधार पर खारिज किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक कठिनाई का मामला नहीं बनाया गया था। इस स्तर पर, मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना फायदेमंद होगा, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से भरोसा किया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आर शेषमल के मामले [1999] 237 आईटीआर 185 में निम्नलिखित माना है (पृष्ठ 187):

"यह वह तरीका नहीं है जिससे राज्य से नागरिकों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है, जो अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का पालन करने की अपनी व्यग्रता में राज्य को अग्रिम कर के रूप में धनराशि का भुगतान करते हैं, भले ही वास्तव में उन्हें धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता न हो और उसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत कार्यवाही बंद कर दिए जाने के बाद गलती से भुगतान की गई धनराशि की वापसी की मांग करते हैं। राज्य ऐसी स्थिति में राशि की वापसी से बचने के लिए सीमा की अति तकनीकी दलील देने का हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 119 बोर्ड को ऐसी स्थिति में न्याय प्रदान करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। बोर्ड ने याचिकाकर्ता के वापसी के अनुरोध को अस्वीकार करके मनमाना काम किया है।"

12. प्रतिवादियों ने आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत रिफंड का दावा करने में देरी के लिए माफी मांगने वाले आवेदन का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि उपचार आदि का विवरण प्रदान किया गया था और गंभीर तपेदिक उस मामले में नरमी का कारण था, क्योंकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है। हालांकि, इस न्यायालय को लगता है कि वरिष्ठ नागरिक/काफी उम्र, अवसाद, जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस तथ्य के साथ कि याचिकाकर्ता कानून/राजस्व संग्रह के गलत पक्ष में नहीं है क्योंकि वह प्रतिवादियों द्वारा किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई का सामना नहीं कर रहा है, और इस प्रकार, वह इस अजीबोगरीब तथ्यात्मक मैट्रिक्स में नरमी से पेश आने का हकदार है। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है कि वर्तमान मामले में दाखिल किए जाने वाले रिटर्न दाखिल करने की अवधि लगभग 15 वर्ष पहले शुरू हुई थी, आरोपित आदेश 2016 का है, यह रिट याचिका पिछले 07 वर्षों से लंबित है और याचिकाकर्ता की आयु लगभग 72 वर्ष है, जो मामले को पूरी तरह से वापस भेजने की गारंटी नहीं देता है। आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के मूल कानून को सीबीडीटी परिपत्र संख्या 09/2015 दिनांक 09.06.2015 के साथ पढ़ा जाए, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट रूप से

दर्शाते हैं कि यदि कोई वास्तविक कठिनाई है, तो छह साल तक की छूट दी जा सकती है।

13. इस मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य और विशिष्ट तथ्यों, जिसमें याचिकाकर्ता की आयु भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 119(2) (बी) के साथ सीबीडीटी परिपत्र संख्या 09/2015 दिनांक 09.06.2015, जो वास्तविक कठिनाई पर 06 वर्ष की देरी के लिए क्षमा निर्धारित करता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एम. मालानी के मामले (उपरोक्त) पर निर्धारित मिसाल कानून को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ राय रखता है कि अवसाद, वृद्धावस्था, मुद्दे का लंबे समय तक लंबित रहना और कर अधिकारियों द्वारा राजस्व संग्रह में कोई नकारात्मकता (जैसे जांच) के साथ याचिकाकर्ता की एक छोटे पैमाने के सर्वेक्षक के रूप में स्थिति को वास्तविक कठिनाई के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, इन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इसे वास्तविक कठिनाई का मामला मानते हुए, 27.02.2017 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है। संबंधित प्राधिकारी रिटर्न स्वीकार करेगा और याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा, जबकि सीबीडीटी परिपत्र संख्या 09/2015 दिनांक 09.06.2015 में निर्धारित याचिकाकर्ता के आवेदन की तिथि से छह वर्ष की सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा, तथा कानून के अनुसार इसे वास्तविक कठिनाई का मामला माना जाएगा।

14. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(मुन्नुरी लक्ष्मण),जे

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।